

वृहद-मेगा श्रेणी के 60 निवेश प्रस्ताव मंजूर

औद्योगिक नीति-2017 : दोनों श्रेणियों में कुल 15969 करोड़ के निवेश की कार्ययोजना

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत अब तक वृहद और मेगा श्रेणी में निवेश के 60 प्रस्तावों को सहमति पत्र (लेटर ऑफ कंफर्ट) जारी हो चुका है। इससे दोनों श्रेणियों में कुल 15969 करोड़ रुपये के निवेश की कार्ययोजना है। इस नीति के तहत आए कुल 125 आवेदनों में 28 प्रस्ताव रद्द हो चुके हैं, जबकि 7 प्रस्ताव रद्द होने की प्रक्रिया में हैं।

दरअसल, राज्य सरकार शीघ्र ही औद्योगिक निवेश के लिए नई नीति

कुल 125 आवेदन मिले, 28 प्रस्ताव रद्द

मेगा श्रेणी में सबसे ज्यादा सीमेंट इकाइयां : मेगा श्रेणी में जिन 34 इकाइयों को सहमति पत्र जारी हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा 19 सीमेंट इकाइयां हैं।

मेगा श्रेणी के उद्योग

कुल आवेदन : 84

कुल स्वीकृत प्रस्ताव : 34

प्रस्तावित निवेश : 14637 करोड़

लाने जा रही है। इससे पहले 13 जुलाई 2017 को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी। इस नीति के तहत लघु एवं मध्यम, वृहद और मेगा श्रेणी के उद्योगों के लिए सुविधा देने की

वृहद श्रेणी के उद्योग

कुल आवेदन : 41

कुल स्वीकृत प्रस्ताव : 26

कुल प्रस्तावित निवेश : 1332 करोड़

व्यवस्था की गई। इस नीति के तहत वृहद श्रेणी में बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये तक पूंजीगत निवेश वाले औद्योगिक उपक्रम रखे गए। वहीं, मध्यांचल व पश्चिमांचल में यह सीमा 150

करोड़ रुपये और गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में 200 करोड़ रुपये तक की रखी गई। इसी तरह से मेगा श्रेणी में बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 100 करोड़ रुपये से अधिक, मध्यांचल व पश्चिमांचल में 150 करोड़ रुपये से अधिक और गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में 200 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश को रखा गया।

वृहद व मेगा श्रेणी के उपक्रमों के लिए पिकप को नोडल संस्था नामित किया गया। सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2017 से अब तक मेगा श्रेणी के उद्योगों के लिए पिकप को 84 आवेदन मिले। इसमें से

33 प्रस्तावों को सहमति पत्र जारी हो चुका है। जबकि, एल्युमिनियम फाइल बनाने का एक प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है।

सहमति पत्र पाने वाले इन मेगा उद्योगों में कुल प्रस्तावित निवेश 14637 करोड़ रुपये का है। वहीं, वृहद श्रेणी में अभी तक 23 निवेश प्रस्तावों को सहमति पत्र जारी हो चुका है। तीन प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। इन उपक्रमों में प्रस्तावित निवेश करीब 1332 करोड़ रुपये का है। इसमें सरकार से सुविधाओं का लाभ लेने के लिए वृहद श्रेणी में 15 और मेगा श्रेणी में 4 आवेदन पिकप को मिले हैं।

अपने पिकप से निवेश करने वाले मेगा